

प्रेषक,

के0डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 24 मार्च, 2015

विषय- जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक-एक स्थायी लोक अदालत में सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश के पत्र सं0-68/XXXVI(1)/2014-23 एक(5)/2005 टी0सी0 दिनांक 12.03.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जिला देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक-एक स्थायी लोक अदालत में सृजित 10 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये दिनांक 01.03.2015 से दिनांक 29.02.2016 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पदों का सृजन मूल रूप में शासनादेश सं0-24 एक(5)/छत्तीस(1)/2005-23 एक(5)/2005 दिनांक 09.11.2005 के द्वारा किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान सं0-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-10-स्थायी लोक अदालत-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-1270/76-दस दिनांक 20.07.1968 सपटित कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07.11.1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय

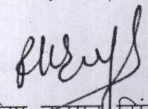
(के0डी0भट्ट)
प्रमुख सचिव

संख्या- 67(1)/XXXVI(1)/2015-23 एक(5)/2005 टी0सी0 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराँय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर।
- 3- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव